गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 200
दि. 21.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दवाओं का सच बेनक़ाब: देश के बाज़ार में फैले 'खामोश ज़हर' ने खोली दवा उद्योग की असल तस्वीर

(जीएनएस)। देश की दवा दुकानों, अस्पतालों और औषधि बाजारों में लाखों लोग रोज़ जिन दवाओं पर निर्भर रहते हैं—उन्हीं दवाओं के अंदर छिपा एक खतरनाक सच अक्तूबर महीने की रिपोर्ट ने सामने रख दिया है। यह सच सिर्फ कानून की कमजोरी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की उस अदृश्य दरार का है, जिसने आम जनता के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट जब सरकार ने सार्वजनिक की, तो ऐसा लगा मानो औषधि बाजार के भीतर वर्षों से छिपे सच पहली बार पूरी ताकत से सामने आना चाहते हों।

रिपोर्ट में कहा गया कि अक्तूबर माह में बाजार से उठाए गए दवा नमूनों में से 63 दवाएँ सीधे-सीधे गुणवत्ता की कसौटी पर असफल पाई गईं। ये वे दवाएँ थीं जिन्हें चिकित्सक मरीज को भरोसे के साथ लिख रहे थे, और मरीज उन्हें उतनी ही सहजता से सेवन करते रहे। लेकिन प्रयोगशालाओं ने बताया कि इनमें से कई दवाओं में शक्ति कम थी, कई की संरचना बिगड़ी हुई थी, कुछ अपनी स्थिरता खो चुकी थीं, और कुछ में वह शुद्धता ही नहीं थी जिसकी उम्मीद एक दवा से की जाती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये दवाएँ लोगों के शरीर में जाकर इलाज नहीं बल्कि धीमी-धीमी क्षति पहुँचा रही थीं, और किसी को पता तक नहीं था।

लेकिन यह तो केंद्र की रिपोर्ट थी। राज्यों की दवा जांच प्रयोगशालाओं ने जब अपना आँकड़ा साझा किया, तो तस्वीर और भी भयावह लगने लगी। राज्यों ने

148 दवाओं को निकृष्ट गुणवत्ता वाला बताया—इसका अर्थ है कि देश के विभिन्न हिस्सों में दवाओं का एक बड़ा हिस्सा वह है जो अपने मूल दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा। एक ओर चिकित्सक मरीज से कहते हैं कि दवा समय पर लें, नियमित लें, पूरी खुराक लें; दूसरी ओर दवा ही अपनी प्रकृति खो चुकी हो, तो इलाज कैसे पूरा होगा?

पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस रिपोर्ट ने एक ऐसा अध्याय खोला जो दवा उद्योग का सबसे ख़तरनाक हिस्सा माना जाता है—फर्जी दवाओं का अध्याय। बिहार और दिल्ली से कुल पाँच सैंपल ऐसे मिले जिन्हें वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से 'स्प्यूरियस' यानी फर्जी घोषित किया। ये दवाएँ असली कंपनियों के नाम से बेची जा रही थीं, लेकिन न निर्माता असली था, न प्रयोगशाला, न पैकिंग, न दवा के अंदर दवा। यह किसी साधारण गलती का मामला नहीं—यह स्वास्थ्य प्रणाली पर सीधा हमला है, जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है, और उन सभी नियमों का मज़ाक है जो मरीज की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, केंद्र और राज्यों की एजेंसियों ने तेजी से दवाओं को बाजार से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई जगहों पर छापे पड़े, कुछ स्टॉकिस्टों की दुकानें सील हुईं, कुछ कंपनियों को नोटिस भेजे गए, और कुछ निर्माताओं की बैच-वार जांच शुरू की गई। यह पूरा अभियान अब एक बड़े संघर्ष का रूप ले चुका है—एक ओर नियामक संस्था हर उस ज़हर को पकड़ना चाहती है जो दवाई का मुखौटा पहनकर बाजार में घूम रहा है, और दूसरी ओर दवा उद्योग का वह हिस्सा है जहाँ लाभ के सामने गुणवत्ता को अक्सर पीछे धकेल दिया जाता है।

जनता के मन में अब एक अनकही आशंका घर कर रही है—जब हर महीने दर्जनों दवाएँ फेल हो रही हैं, तो क्या यह समस्या बढ़ती नहीं जा रही? क्या दवाओं का यह संकट धीरे-धीरे उस दिशा में नहीं जा रहा जहाँ एक दिन भरोसा ही टूट जाएगा? क्या यह चिंता इस बात का संकेत नहीं कि दवा उद्योग में कहीं न कहीं गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला पहरा कमजोर पड़ा है?

जिस देश में करोड़ों लोग अपनी बीमारी की आखिरी उम्मीद दवा को मानते हैं, वहाँ दवा का हर दोष सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार पर चोट है। मरीज यह नहीं जान सकता कि जो गोली वह निगल रहा है, वह उपचार देगी या शरीर को भीतर से खोखला कर देगी। डॉक्टर यह नहीं जान सकता कि जो दवा वह लिख रहा है, वह प्रभावी है या नहीं। और सरकार यह अनुमान नहीं लगा सकती कि अगले महीने कितनी दवाएँ फिर इसी सूची में शामिल होंगी। यह पूरा घटनाक्रम एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है—दवाओं और ज़हर के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं है, जितनी दिखती है। और दुर्भाग्य यह है कि यह रेखा हर महीने थोड़ा और धुंधली होती जा रही है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ दवा की बोतल में बीमारी छिपी हो सकती है, और इलाज के नाम पर जोखिम पीछे-पीछे चलता हो सकता है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन-सी दवा खराब निकली, असली प्रश्न यह है कि आम जनता किस पर भरोसा करे—दवा पर, या नियमन पर, या किसी ऐसी व्यवस्था पर जो हर महीने अपनी कमजोरी खुद उजागर कर रही है? दवा की दुनिया में यह संकट केवल आज का नहीं—यह आने वाले कल का भी डर है। और अब यह समय आ चुका है कि देश दवाओं के इस 'खामोश ज़हर' के खिलाफ उतने ही संकल्प के साथ खड़ा हो, जितने संकल्प से मरीज दवा पर भरोसा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आत्म-संशोधन: राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर बड़ा फैसला, न्यायपालिका ने कहा-संविधान की चुप्पी को अदालत भर नहीं सकती

(जीएनएस)। भारत की सर्वोच्च अदालत में मंगलवार का दिन उस अध्याय की तरह दर्ज हुआ, जो न केवल न्यायिक इतिहास की दिशा बदलने वाला है, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे की गहराइयों में छिपी कई जटिलताओं को भी उजागर करता है। दिल्ली में बैठे संविधान की पांच जजों वाली पीठ ने अपने ही पूर्व निर्णय को असंवैधानिक ठहराते हुए यह साफ कर दिया कि न्यायपालिका भले ही संविधान की रक्षा की अंतिम चौकी हो, लेकिन वह संविधान में मौन पड़े प्रावधानों के स्थान पर अपने नियम नहीं गढ़ सकती। अदालत ने कहा कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा तय करने का अधिकार सिर्फ संविधान निर्माता के पास था; यह सत्ता न तो अदालत को दी गई है और न किसी अन्य संस्था को।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ—जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय चांदूरकर शामिल थे—ने राष्ट्रपति के आर्टिकल 143 के तहत भेजे गए 14 सवालों के विस्तृत रेफरेंस पर विचार करते हुए यह ऐतिहासिक राय दी। अदालत ने माना

कि पिछले वर्ष दो जजों की बेंच द्वारा तमिलनाडु के दस विधेयकों को "डीम्ड असेंट" यानी स्वतः स्वीकृति मान लेने का फैसला न केवल संविधान की भाषा के विरुद्ध था बल्कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी ठेस पहुँचाता था। संविधान उन संस्थाओं के बीच संतुलन का ग्रंथ है—और यह अदालत का काम नहीं कि वह संतुलन को अपने आदेशों से एक दिशा में झुका दे।

पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल को विधेयक वापस भेजने, रोक कर रखने या राष्ट्रपति के पास भेजने का जो विवेकाधिकार संविधान ने दिया है, उसे अदालत सीमित नहीं कर सकती। यदि न्यायपालिका राज्यपाल को समय-सीमा निर्धारित कर देगी, तो इसका अर्थ होगा कि वह कार्यपालिका की भूमिका में हस्तक्षेप कर रही है, जो कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में स्वीकार्य नहीं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्यपालों द्वारा बिलों को अनिश्चित समय तक रोक कर रखना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं—लेकिन इसका समाधान न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमा निर्धारित करना नहीं हो सकता।

हालाँकि अदालत ने यह भी माना कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति विधेयकों को अव्यवहारिक रूप से लंबे समय तक लंबित रखें और उसका कोई उचित कारण भी न दें, तो अदालत न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा हस्तक्षेप केवल इस बात के लिए होगा कि संवैधानिक पदाधिकारी अपना निर्णय दें—अदालत यह तय नहीं करेगी कि निर्णय क्या होना चाहिए। यह विभाजन उस लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा के लिए है जो संविधान ने तीनों स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के बीच निर्धारित की है।

इस फैसले की पृष्ठभूमि भी उतनी ही रोचक है। पिछली बेंच ने 10 तमिलनाडु विधेयकों को बिना राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के "स्वीकृत" मान लिया था और यह कहा था कि संविधान की चुप्पी उस स्थिति में अदालत को समय-सीमा तय करने से नहीं रोकती। उसी निर्णय ने पूरे देश में संवैधानिक बहस को जन्म दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई को सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या वास्तव में संवैधानिक मौन को न्यायपालिका अपने आदेशों से भर सकती है? क्या अनुच्छेद 142—जो अदालत को संपूर्ण न्याय प्रदान करने की असाधारण शक्ति देता है—इस तरह राजनीतिक क्षेत्र के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है?

संकुरु नदी का त्रासदी भरा सफर: नाव पलटने के बाद 64 लोग लापता, कांगो में गूँज रही दर्द की चीख

(जीएनएस)। अफ्रीकी महाद्वीप के हृदय में बसे कांगो गणराज्य के कसाई प्रांत की संकुरु नदी इन दिनों एक भयावह हादसे की गवाह बन गई है। नदी की शांत लहरों में बहती एक साधारण सी मालवाहक नाव देखते ही देखते गहरे जल में समा गई और उसके साथ समा गए वे सपने, वे चेहरे, वे जीवन—जो राजधानी किंशासा पहुँचने की आशा लिए यात्रा पर निकले थे। इस भीषण हादसे में कम से कम 64 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि बचाए जा सका है केवल 50 को। कुल मिलाकर नाव में लगभग 120 मुसाफ़िर सवार थे।

स्थानीय अधिकारियों की मानें तो 13 नवंबर को यह नाव संकुरु प्रांत के बेना डिबेले बंदरगाह से निकली थी। यात्रा लगभग 800 किलोमीटर लंबी थी, जिसे पार करते हुए यह नाव लोगों, माल और उम्मीदों को लेकर धीरे-धीरे राजधानी की ओर बढ़ रही थी। लेकिन संकुरु नदी का स्वभाव उस दिन कुछ और ही था। रिपोर्ट के अनुसार, नाव एक गहरे "पानी के भंवर" में फंस गई। भंवर ने कुछ ही क्षणों में नाव को असंतुलित कर दिया और

देखते ही देखते वह पलट गई।

हादसे की अचानकता इतनी तीव्र थी कि कई यात्री गहरे पानी में बिना किसी चेतावनी के समा गए। स्थानीय अधिकारी और बचावकर्मी लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन नदी की तेज़ धारा और अपरिहार्य परिस्थितियों के बीच लापता यात्रियों को खोज पाना बेहद कठिन बताया जा रहा है। बचाव अभियान में शामिल एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि अब किसी के जीवित बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन खोज अभियान जारी रहेगा।

कांगो में नदीय यात्रा आम बात है। सड़कें और आधारभूत ढाँचों की कमी के चलते लोग अक्सर नदी के रास्ते ही लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसी नावें आमतौर पर भारी भीड़ से भरी होती हैं और सुरक्षा संबंधी उपाय अक्सर अत्यंत सीमित होते हैं। यही कारण है कि कांगो में नदी हादसे बार-बार दर्दनाक रूप लेकर सामने आते हैं। इस त्रासदी ने स्थानीय परिवारों को पूरी तरह झकझोर दिया है। बेना डिबेले से लेकर किंशासा तक लोगों की आँखें अपने खोए हुए परिजनों की खोज में नदी की ओर टिकी हैं। घरों में मातम पसरा है और पूरे कसाई प्रांत में एक गहरी चुप्पी है—एक ऐसी चुप्पी जो उस पीड़ा को बयान नहीं कर सकती, जो इस हादसे ने जनजीवन में भर दी है।

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हादसे की जांच की जाएगी और ऐसे हादसों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएँगे, लेकिन सच यह है कि संकुरु नदी ने जो जीवन निगले हैं, वे कभी लौटकर नहीं आएँगे। कांगो एक बार फिर उस दर्द से गुजर रहा है जो उसकी नदियों के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ है—असुरक्षित यात्रा, लापरवाही, और अंधकार में खोती अनगिनत ज़िंदगियाँ।

संकुरु के इस हादसे ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कब तक नदी का रास्ता चुनने वाले लोग अपनी मंज़िल से पहले ही मौत के समंदर में समाते रहेंगे।

व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक मुलाकात : ट्रंप और जोहरान ममदानी आमने-सामने, भारतवंशी मेयर की बढ़ी वैश्विक पहचान

(जीएनएस)। अमेरिकी राजनीति में इन दिनों एक अप्रत्याशित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के निर्वाचित मेयर बने भारतीय मूल के जोहरान ममदानी—जो पिछले कई वर्षों से ट्रंप प्रशासन के मुखर आलोचक रहे हैं—अब व्हाइट हाउस में आमने-सामने बैठकर बातचीत करने जा रहे हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि अमेरिका की बदली हुई राजनीतिक जमीन, बहुजातीय नेतृत्व और बदलती शक्ति संरचना का प्रतीक मानी जा रही है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि ममदानी के आग्रह पर व्हाइट हाउस में शुक्रवार को मुलाकात तय हो गई है। ट्रंप ने कहा कि बैठक की विस्तृत जानकारी और उसके परिणाम बाद में साझा किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कई वर्षों से ममदानी ट्रंप के सामाजिक और आव्रजन संबंधी नीतियों पर तीखी आलोचना करते रहे हैं।

जोहरान ममदानी—जिन्हें न्यूयॉर्क की जनता ने हाल में ही भारी समर्थन के साथ महापौर चुना—भारतवंशी समुदाय के एक नए, प्रगतिशील और बहुभाषी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था। उनकी माँ मीरा नायर दुनिया की प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशकों में गिनी जाती हैं और उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सात साल की उम्र में परिवार के साथ न्यूयॉर्क आकर बसने के बाद ममदानी ने अपनी पढ़ाई और राजनीतिक सफर यहीं से आगे बढ़ाया। 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की और इसके बाद शहर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय होकर तेजी से लोकप्रिय हुए।

इस मुलाकात की पृष्ठभूमि और भी रोचक है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही यह संकेत दिया था कि वह ममदानी से वाशिंगटन में मिलेंगे, लेकिन उस समय तारीख की घोषणा नहीं हुई थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक अमेरिकी राजनीति के भविष्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिकी समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की स्थिति, आव्रजन नीतियों में चल रहे बदलाव, न्यूयॉर्क सिटी के प्रशासनिक सुधार, और भारत-अमेरिका संबंधों में नई संभावनाएँ—ये सभी मुद्दे बैठक की संभावित चर्चा सूची में शामिल बताए जा रहे हैं।

ममदानी के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है और वे व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए उत्साहित हैं। यह मुलाकात दो अलग-अलग विचारधाराओं वाले नेताओं के बीच संवाद की राहें खोल सकती है, और यह संकेत दे सकती है कि अमेरिकी राजनीति में संवाद का स्थान अभी भी जीवित है, चाहे मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हों। यह मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि अमेरिका के भविष्य, विविधता और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक नया अध्याय लिखने जैसा क्षण बन सकती है।

चीता संरक्षण में नई सुबह: भारत में जन्मी 'मुखी' बनी आशा की जननी, पाँच नन्हे शावकों ने बढ़ाया देश का गौरव

(जीएनएस)। भारत के वन्यजीव संरक्षण की लंबी और रोमांचक यात्रा में आज एक ऐसा दिन दर्ज हुआ, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मध्य भारत की धरती पर जन्मी मादा चीता 'मुखी' ने पाँच स्वस्थ शावकों को जन्म देकर न केवल वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों को उत्साह से भर दिया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी विदेशी चीतों के लिए केवल आश्रय स्थल ही नहीं, बल्कि नया घर बन सकती है। यह एक ऐसा चमत्कार है, जिसकी कल्पना कई दशक पहले असंभव मानी जाती थी, क्योंकि भारत में चीतों की अंतिम झलक 1952 में दर्ज की गई थी और उसके बाद यह प्रजाति देश से विलुप्त घोषित कर दी गई थी।

लेकिन बदलते समय के साथ भारत ने, अपनी पारंपरिक जैव विविधता की रक्षा के संकल्प के साथ, न सिर्फ अफ्रीकी चीतों को लाकर उन्हें नई ज़मीन पर बसाने का अभियान शुरू किया बल्कि उन्हें यहाँ के मौसम, यहाँ की भोजन श्रृंखला और यहाँ के जंगलों से परिचित कराने का कठिन प्रयास भी किया। यही प्रयास आज 'मुखी' के पाँच बच्चों के रूप में फलित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक क्षण को साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उस विश्वास का परिणाम है जिसके बल पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि संरक्षण केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि क्रियान्वित की जाने वाली ज़िम्मेदारी है। भूपेंद्र यादव द्वारा 'एक्स' पर साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में मुखी अपने नवजात शावकों के साथ बिलकुल शांत, संरक्षक के भाव में दिखाई देती है। मंत्री ने इसे भारत के "प्रोजेक्ट चीता" के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक बताया। यह पहला अवसर है जब भारत में जन्मी किसी मादा चीता ने स्वदेशी धरती पर अपना पहला कुनबा बढ़ाया है। पाँच शावक—जो जीवन की नन्ही साँसों के साथ भविष्य की संभावनाओं को धारण किए हुए हैं—यह प्रमाण बनकर उभरे हैं कि भारत के जंगल अब केवल चीतों के लिए अनजान स्थान नहीं रहे, बल्कि उनकी सहज विकास भूमि बनते जा रहे हैं। यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भावनात्मक भी। एक लंबे अरसे तक यह सवाल उठता रहा कि क्या अफ्रीकी चीते, भारतीय पारिस्थितिकी के तापमान, वर्षा, मानव गतिविधियों और शिकार की विविधता के बीच सफलतापूर्वक अनुकूलित हो सकेंगे? क्या उन्हें पर्याप्त ग्रास उपलब्ध होगा? क्या वे अपने प्राकृतिक व्यवहार को संरक्षित रख पाएँगे? लेकिन मुखी के इन पाँच नवजात शावकों ने सिद्ध कर दिया कि प्रकृति यदि सही वातावरण पाए तो अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है। वन विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के अनुसार, मुखी और उसके शावक पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह स्वस्थ प्रसव इसलिए भी बड़ा संकेत है क्योंकि यह दिखाता है कि नए वातावरण में रहने के बावजूद चीतों पर खाद्य, तापमान या बीमारी जैसे किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। यह आनुवंशिक विविधता बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इस नए कुनबे में भारत के जंगलों में जन्मे चीतों की नई पीढ़ी तैयार होगी—जो आने वाले दशकों में देश की जैव विविधता को नए आयाम दे सकती है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

नक्सल के नासूर पर प्रहार

इसमें दो राय नहीं है कि शीर्ष माओवादी कमांडर हिडमा का मुठभेड़ में मारा जाना वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ देश की दशकों पुरानी लड़ाई में निर्णायक सफलताओं में से एक है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर प्रहार से देश नक्सली हिंसा से मुक्ति की राह में कामयाबी की तरफ बढ़ा है। लगभग तीन दशकों तक हिडमा बस्तर में चौंकाने वाली रणनीतियों से बड़े हमलों को अंजाम देता रहा है। बताते हैं कि वह सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा हिडमा व उसकी पत्नी समेत छह नक्सलियों को मार गिराना केंद्र सरकार की उस रणनीति की सफलता को दर्शाता है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया था। इसी साल मार्च में बीजापुर में जब 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था तब गृहमंत्री अमित शाह ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए सभी का पुनर्वास करके, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही थी। निस्संदेह, हिडमा का सफाया नक्सलवादी संचालन ढांचे के खात्मे और भारत में उग्रवाद विरोधी तंत्र की एक महत्वपूर्ण जीत का संकेत है। गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 के कमांडर के रूप में हिडमा का उदय- वंचित युवाओं की भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और हथियार बनाने की उग्रवादी क्षमता का प्रतीक रहा है। उसकी गिनती सबसे खूंखार नक्सलवादी कमांडर के रूप में होती रही है। अब वर्ष 2010 का दंतेवाड़ा हमला हो या 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले बीस वर्षों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा की रणनीति बतायी जाती है। वहीं दूसरी ओर इन हमलों ने भारत की सुरक्षा रणनीति को नया रूप दिया। इससे पहले इसी साल मई में सुरक्षाबलों ने माओवादी संगठन के जनरल सक्रेटरी बसवराजू को भी मार गिराया था। वहीं इस साल विभिन्न मुठभेड़ों में तीन सौ से अधिक नक्सली मारे जाने से नक्सलवाद छोटे इलाके में सिमटा है।

निस्संदेह, सुरक्षा बलों की तत्परता और सुनियोजित अभियानों से नक्सलवाद कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जरूरत उन परिस्थितियों को दूर करने की है, जिन्होंने नक्सलवाद को जन्म दिया। आवश्यकता उन मुद्दों के समाधान की है, जिसके चलते माओवाद को जड़ें जमाने का मौका मिला। बस्तर का अधिकांश क्षेत्र लगातार विकास की विसंगतियों, खनन से संसाधनों के मनमाने दोहन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण विस्थापन व जनजातीय समुदायों और राज्य के बीच विश्वास की कमी से जूझता रहा है। अभी भी आदिवासियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, भूमि अभिलेखों और कल्याणकारी योजनाओं तक पूरी तरह पहुंच नहीं बन पायी है। दूर-दराज के कई गांवों में ग्रामीणों को प्रशासन का अनुभव नागरिक संस्थानों के बजाय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ही होता है। दरअसल, विकास की नीतियों से जुड़े वायदों और हकीकत का अंतर ही आदिवासियों में असंतोष को बढ़ाता है। भले ही माओवाद का प्रभाव कम हो जाए। वास्तव में जब तक शासन जिम्मेदार, जवाबदेह और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं बन पाता, तब तक माओवादी संस्कृति के पनपने की आशंकाएं बनी रहेंगी। दरअसल,क्षेत्र में तंत्र की अनुपस्थिति ने ही चरमपंथियों को आदिवासियों के रक्षक के रूप में पेश करने का मौका दिया। निस्संदेह, सुरक्षा बलों ने माओवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा काम कर दिया है, अब राज्यों के पास इस रणनीतिक जीत को स्थायी शांति में बदलने का अच्छा अवसर है। इसकी प्राप्ति के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि सड़कें, स्कूल, नागरिक अधिकार व आजीविका बस्तर के वनाच्छादित इलाकों तक पहुंचे। तभी देश नक्सली हिंसा के दंश से भविष्य में मुक्त रह पाएगा। अभी नक्सवादियों पर जो चौतरफा दबाव बना है और जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके निहितार्थों को स्थायी बनाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जारी सघन अभियान से बच निकलकर नक्सली देश के अन्य राज्यों में नये ठिकाने न तलाश लें। साथ ही समर्पण करने वाले नक्सलियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के संवेदनशील प्रयास भी बेहद जरूरी हैं।

नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार एक नई सुबह की आहट

"आतंकवाद की तरह ही नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, गहरी और जटिल चुनौती रहा है। जिस तरह सीमा पार से आने वाला आतंकवाद देश की शांति, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था, उसी तरह भीतर से जन्मा नक्सलवाद राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता रहा।

नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है और यह बड़ी उपलब्धि एवं परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुनियोजित, कठोर और व्यापक रणनीतियों का परिणाम है। वर्षों से जिस समस्या ने भारत के हृदयस्थल को रक्तरंजित किया था, जिस विचारधारा ने दशकों तक विकास, सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को बंधक बनाए रखा था, वह अब लगभग समाप्ति की कगार पर पहुँच चुकी है। इसका सबसे बड़ा और हालिया प्रमाण है देश के सबसे खतरनाक, खूंखार और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का खात्मा, एक ऐसा नाम जिसके आतंक ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि पूरे तंत्र को लंबे समय तक चुनौती दी। सुकमा क्षेत्र में जन्मा हिड़मा, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 का प्रमुख। उसकी मौजूदगी मात्र से बड़े-बड़े हमले अंजाम दिए जाते थे। 2010 का दंतेवाड़ा हो या फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले 20 बरसों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा का हाथ माना जाता है। उसने लंबे अरसे तक दंडकारण्य में आतंक का राज कायम रखा। दरभा घाटी नरसंहार तक, सुरक्षा बलों के कई घातक ऑपरेशनों का गुनाहगार हिड़मा रहा। उसकी धमक इतनी थी कि उसके सिर पर 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों के एक अत्यंत सटीक और साहसपूर्ण अभियान में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे सहित छह माओवादी ढेर हुए। मौके से मिली एके-47, पिस्टल, राइफलें और अन्य हथियार यह प्रमाणित करते हैं कि यह ऑपरेशन नक्सलवाद की रीढ़ पर निर्णायक प्रहार है। हिड़मा का अंत प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक ऐसा क्षण है जिसने नक्सली नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। लंबे समय से 'लाल गलियारा' कहे जाने वाले क्षेत्र की गतिविधियाँ जिस तेजी से सिकुड़ रही हैं, वह

दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर जिस दोहरी रणनीति को अपनाया है, उसने वास्तविक जमीन पर असर दिखाया है। मार्च 2026 तक 'नक्सलमुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत इस साल 300 नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और आत्मसमर्पण किया-यह आँकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब अपनी वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति खो चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो दिनों में सैकडों नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना यह दर्शाता है कि नक्सल संगठन अब अपने आधार क्षेत्रों में भी समर्थन खो रहा है, और आदिवासी समाज धीरे-धीरे सरकारी विकास योजनाओं की ओर बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है हिड़मा का खात्मा, जिसने माओवादी कमान में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई उनके लिए आसान नहीं होगी।

आतंकवाद की तरह ही नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, गहरी और जटिल चुनौती रहा है। जिस तरह सीमा पार से आने वाला आतंकवाद देश की शांति, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था, उसी तरह भीतर से जन्मा नक्सलवाद राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता रहा। दशकों तक यह समस्या न सिर्फ कुछ राज्यों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता और असुरक्षा का कारण रही। लेकिन अब जिस निर्णायक मोड़ पर देश खड़ा है, वह यह संकेत देता है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। हाल के वर्षों में लगातार मिल रही सफलताएँ, शीर्ष नक्सली कमांडरों का सफाया, व्यापक आत्मसमर्पण, और प्रभावित क्षेत्रों में तेज विकास-ये सभी इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि देश एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह वह सुबह है जो भारत को भय, हिंसा और पिछड़ेपन से मुक्त कर, स्थायी शांति और तेज विकास की ओर ले जाती है।

नक्सलवाद की जड़ें स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भूमि अधिकारों और आदिवासी इलाकों की उपेक्षा में थीं। कई क्षेत्रों में विकास की रोशनी नहीं पहुँची थी, सरकारी योजनाएँ कागज़ों में रह जाती थीं, और स्थानीय समुदाय प्रशासन के प्रति अविश्वास से भरे हुए थे। इस वातावरण में नक्सली संगठनों को जमीन और जनसमर्थन मिला। उन्होंने वर्ग संघर्ष और हथियारबंद क्रांति के नाम पर हिंसा का मार्ग अपनाया, जंगलों को अपनी ढाल बनाया और आदिवासी युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे-धीरे यह आंदोलन एक साम्यवादी विचारधारा का रूप लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन गया। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपनी मूल विचारधारा से हटकर आतंक, वसूली, शोषण और खून-खराबे का अड्डा बन गया। सुरक्षा बलों पर हमले, विकास कार्यों को बाधित करना, पुलों और स्कूलों को उड़ाना, आदिवासियों को ढाल बनाना, और सत्ता हासिल करने की लालसा-यह सब नक्सलवाद की असलियत बन गया। इस मानसिकता ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि हजारों परिवारों को तबाह किया और लाखों लोगों के जीवन को भय से भर दिया। लेकिन मोदी एवं शाह के प्रयासों से न केवल नक्सलवाद के खात्मे की सफल लड़ाई लड़ी गयी बल्कि नक्सल क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को लागू किया गया। सड़क-बिजली-मोबाइल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काफी काम हुआ है और इससे भी नक्सलियों की पकड़ कमजोर करने में मदद मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 हजार किमी से ज्यादा सड़कें बनी है, बैंकों की हजार से ज्यादा शाखाएं खोली गई है और स्किल डिवेलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन समन्वित प्रयासों से ही नक्सली जड़ से उखड़ेंगे।

माड़वी हिड़मा जैसे अत्यंत खूंखार और रणनीतिक दिमाग वाले नेता का मारा जाना, नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने जैसा है। हिड़मा न सिर्फ नक्सलियों की सैन्य रणनीतियों का प्रमुख दिमाग था, बल्कि उसकी छवि ने वर्षों तक सुरक्षा बलों में चुनौती की भावना जगाई रखी। नक्सलवाद के कमजोर होने में केवल सुरक्षा अभियानों की भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण रही है। जब सरकार ने स्पष्ट किया कि देश को "नक्सलवाद मुक्त भारत" बनाना है, तो उसके लिए बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई गई। एक ओर सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सटीक इंटेलिजेंस से मजबूत किया गया, वहीं दूसरी ओर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, दूरसंचार और आजीविका कार्यक्रमों द्वारा विकास को तेज़ किया गया। विकास और सुरक्षा का यह संयुक्त प्रभाव नक्सलवाद की जड़ों को खोखला करने में निर्णायक सिद्ध हुआ है।

देश के सामने जो नई सुबह उभर रही है, उसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि बंदूकें शांत हो जाएँगी। इसका अर्थ यह भी है कि वे क्षेत्र, जो दशकों से पिछड़े थे, अब देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। वहाँ निवेश होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा, पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और लोग भय-मुक्त होकर जीवन जी पाएँगे। नक्सलवाद के पतन का संदेश यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी हिंसक विचारधारा से अधिक शक्तिशाली है। हथियार, भय और आतंक से सत्ता पाने का कोई भी प्रयास अंततः असफल होता है। जनता की आकांक्षाएँ सदैव विकास, सुरक्षा और शांति में होती हैं। नक्सली आंदोलन की जैसी समाप्ति दिख रही है, वह इस सत्य को और अधिक स्पष्ट करती है। नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति केवल बंदूक से नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार विकास योजनाओं की निरंतरता बनाए रखे, आदिवासी समुदायों को सशक्त करे, स्थानीय संस्कृति और संसाधनों का सम्मान करे, और यह सुनिश्चित करे कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और संवेदनशील बने। यदि यह निरंतरता जारी रहती है, तो नक्सलवाद का पुनरुत्थान असंभव हो जाएगा। नक्सलवाद का लगभग खत्म होना भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह उस संघर्ष का अंत है जिसमें हजारों जवानों ने बलिदान दिया, लाखों नागरिकों ने दशकों तक आतंक सहा, और देश ने विकास की गति रोककर भी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज जब नक्सलवाद ढह रहा है, तब यह केवल सरकार की सफलता नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक विजय है। यह एक नए भारत की सुबह है-शांत, सुरक्षित, विकासशील और आत्मविश्वासी। ऐसी सुबह जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रकाश से भर देगी।

प्रेरणा

संस्कारों का उजाला, एक बालक और इतिहास की मौन पुकार

स्कूल का वह दिन हर दिन जैसा ही शुरू हुआ था, पर उसके भीतर कुछ अलग ही हलचल थी। शिक्षक ने घोषणा की थी कि आज पूरी कक्षा को उस ऐतिहासिक स्थल पर ले जाया जाएगा जहाँ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अनेक वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर किया था। बस धीरे-धीरे धूल उड़ाती आगे बढ़ रही थी, पर छात्र का मन तेज़ी से दौड़ रहा था। खिड़की से बाहर झाँकते हुए उसे लगता था जैसे पेड़ों की लंबी छायाएँ उसे किसी पुराने, भुला दिए गए समय की ओर बुला रही हों।

जब बस रुकी, छात्र अपने साथियों के साथ नीचे उतरा। सामने एक पत्थर का चबूतरा था, जिसके ऊपर वीरों की प्रतिमा खड़ी थी—सीधी, गंभीर, अडिग। वह प्रतिमा मानो हवा में गुँथे साहस और त्याग को साकार कर रही थी। छात्र ने मन ही मन अपनी साँस थाम ली। उसके भीतर किसी अनसुने इतिहास की खामोशी उतरने लगी थी।

शिक्षक ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया और उन वीरों की कथा समझानी शुरू की। शिक्षक की आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द तीर की तरह दिल को छूता जा रहा था—कैसे युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी ने स्वतंत्रता के नाम पर अत्याचार सहा; कैसे किसी ने अपने परिवार को छोड़ा, किसी ने अपनी धरती को, और अंत में कई लोगों ने अपनी अंतिम साँस तक अपने देश को समर्पित कर दिया।

छात्र के भीतर भावनाओं की लहरें उठने लगीं। वह प्रतिमा को देखता रहा—लेकिन अब वह प्रतिमा धातु नहीं थी, वह उन शहीदों का साकार रूप थी, हवा में अब भी उनकी शपथ की आग तैर रही थी, और धरती मानो उनके रक्त के दागों से काँप रही थी।

वह धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। उसका मन इतना भारी था कि वह वहीं पार्क की पतली-सी सड़क पर लगी सीमेंट की बेंच पर आकर बैठ गया। जूते पहनने के बाद भी उसके कदमों में कुछ संकोच था, जैसे वह इस भूमि पर चलते हुए भी उसे चोट पहुँचा रहा हो।

वह फिर से प्रतिमा की ओर देखने लगा—अचानक उसे लगा कि प्रतिमा उसे कुछ कहना चाहती है। एक मौन, पर बहुत गहरी बात शायद यह कि बलिदान केवल इतिहास नहीं होता, वह वर्तमान और भविष्य के लिए एक गर्व का संधान होता है।

इसी मौन संवाद के बीच उसने देखा कि तीन-चार लोग उसी सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। एक ने हैट पहन रखी थी, कैमरा थामे था, और बाकी दो सिगार पीते हुए हँसी-मज़ाक करते आगे बढ़ रहे थे। वे सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर प्रतिमा के पास जा खड़े हुए—जूते पहने, धुआँ उड़ाते, जैसे यह कोई साधारण पार्क की मूर्ति हो।

छात्र के मन में एक तीखा दर्द उठा। वह संस्कारों से सीखा था कि पवित्र स्थलों पर जूते उतारना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आदर का मौन प्रण है। किसी क्षेत्र की पवित्रता उसके पत्थरों में नहीं होती—वह उन आत्माओं में होती है जिनके खून और सपनों ने उसे पवित्र बनाया होता है।

वह बेंच से उठा। धीरे-धीरे उन लोगों के पास गया, उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी, पर उसका मन दृढ़ था। उसने विनम्रता से कहा—

"यह स्थान बहुत पवित्र है। आपको यहाँ नंगे पैर आना चाहिए था। ऐसे स्थलों पर जूते-चप्पल उतार देना सम्मान होता है।"

उसके शब्द किसी आदेश की तरह नहीं थे, बल्कि किसी गहरे संस्कार की चमक थे। उन लोगों ने भले ही यह बात गंभीरता से ली या नहीं, पर उस क्षण में एक मासूम किशोर ने इतिहास का सम्मान अपने कर्तव्य से बड़ा मान लिया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका यह स्वभाव, यह संवेदनशीलता, यह दृष्टि आगे चलकर उसके जीवन की भाषा बन जाएगी। वह दुनिया को केवल आँखों से नहीं, आत्मा से देखना सीख जाएगा।

वर्ष बीतते गए। वह छोटा-सा छात्र बड़ा हुआ, उसकी आँखों में वही गहराई बनी रही जो शहीद स्थल की धूल और प्रतिमा की छाया ने उसे दी थी। और फिर एक दिन उसने कैमरा उठाया—पर उसके हाथ में वह कैमरा सिर्फ मशीन नहीं था, वह उसकी आत्मा का दर्पण था।

आगे चलकर वही बालक पूरी दुनिया में जाना गया—महान फिल्मकार, मानवता की धड़कन को सजीव करने वाले कलाकार—सत्यजीत रे के नाम से।

यह कहानी बताती है कि महानता किताबों से नहीं आती, पुरस्कारों से नहीं आती—वह उन पलों से जन्म लेती है जहाँ हृदय संवेदना से थरथराता है और आत्मा सम्मान से भर जाती है। संस्कार कोई बोझ नहीं, बल्कि एक प्रकाश है—जो मनुष्य के भीतर जलता है और उसकी यात्रा को उजाला देता चलता है।

यही संस्कारों की वास्तविक शक्ति है—वे मनुष्य को भीतर से महान बनाते हैं, चुपचाप, धीरे-धीरे, लेकिन सदा के लिए।

आतंकवादी गतिविधियों का माध्यम बनते टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म

सहज संवाद और एक दूसरे को जोड़ने का प्रमुख माध्यम सोशल मीडिया आज आतंकवादी गतिविधियों का भी सुरक्षित एवं गोपनीय माध्यम बनता जा रहा है। हालिया दिल्ली ब्लास्ट में लिप्त व्हाइट कॉलर आतंकवादियों के परस्पर संवाद का माध्यम टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पाया गया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की यह अति अवस्था है। न्यूयार्क टाइम्स ने एक अध्ययन में 3.2 मिलियन संवादों का विश्लेषण किया है। वहीं जानकारों के अनुसार टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ही 1500 से अधिक नस्लवादी चैनल सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इतनी अधिक संख्या में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त चैनलों का सक्रिय होना गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। मानवता के लिए सबसे सम्माननीय डाक्टरी का पेशा दिल्ली ब्लॉस्ट और इसके बाद दिन प्रतिदिन खुलती परतों से बेनकाब होता जा रहा है। डाक्टर जिसका जीवन बचाने का दायित्व है वहीं लोगों की मौत का सौदागर बनता है तो यह मानवता के लिए शर्मनाक स्थिति है। मजे की बात यह है कि शिक्षा का केन्द्र विश्वविद्यालय इसका केन्द्र बना हुआ पाया गया। हांलांकि फरीदाबाद के अलफलाह विश्वविद्यालय ने अपने आपकों आतंकवादी गतिविधियों से दूर और साफ-सुथरा होने का दावा किया है पर यह महज लिपापोती से अधिक कुछ ज्यादा नहीं लगती। मजे की बात यह है कि जब डॉक्टर बेनकाब हो रहे हैं और इनपर कार्रवाई की बात हो रही है तो कुछ राजनीतिक दल और संगठन इनके पक्ष में दूसरी तरह की भाषा बोलने लगे हैं। समझ से परे यह बात है कि ऐसे संगठनों का क्या दायित्व उन बेगुनाह लोगों और परिवारों के प्रति नहीं होता क्या जो इन आतंकी गतिविधियों में अकारण मौत के आगोश में चले जाते हैं तो बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। इन प्रभावित लोगों व इनके परिवारों के प्रति भी किसी की जबावदेही होनी चाहिए। अच्छा तो यह हो कि दूसरी तरह की भाषा बोलने वाले प्रभावित लोगों के पक्ष में भी आगे आएं। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों के साझा संवाद का माध्यम टेलीग्राम प्लेटफार्म पाया गया है। सोशल मीडिया की जहां तक बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों की पसंद, सूचनाओं को साझा करने और एक दूसरे तक अपनी भावनाएं पहुंचाने का माध्यम बन गए हैं। सवाल इनके दुरुपयोग और इन पर आवष्यक अंकुश की आवश्यकता को लेकर है। लाख दावें करें पर यह प्लेटफार्म असामाजिक गतिविधियों व भ्रामक समाचारों पर तत्काल कार्रवाई करने में विफल ही देखें गए हैं। सोशल मीडिया के संदेशों की प्रतिक्रिया स्वरुप लोगों के जुटजाने और भीड़ के आक्रोशित हो जाना आज आम हो गया है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था के जिम्मेदार सबसे पहले उस क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को स्थगित करना ही श्रेयस्कर समण्ते हैं। यह भी सही है कि देश में अधिकांश लोगों से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का संचालन विदेशी धरती पर हो रहा है। इसे दुर्भाग्यजनक ही माना जाएगा कि लाख प्रयासों के बावजूद देश में बने सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी पहचान बनाने व अधिकांश देशवासियों के चहेते बनने में सफल नहीं हो पाए। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंकड्विन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्रास या ट्वीटर, ठिकटॉक, स्नेपचेट, पिंटरेस्ट, वीचैट, रेडिट, टेलीग्राम आदि आदि प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म की संचालन की ड़ोर विदेशियों के हाथ ही है। हांलाकि हमारे देश में यूट्यूब, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक्डइन आदि सोशल प्लेटफार्म अधिक चलन में है तो वाट्सएप और इंस्टा की पहुंच आम लोगों तक है। दुनियाभर में 5 अरब 41 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक टेलीग्राम प्लेटफार्म का सवाल है यह सर्वविदित है कि आतंकवादी गतिविधियों का यह केन्द्र रहा है। रुस यूक्रेन युद्ध में जेलेन्स्की द्वारा इस प्लेटफार्म का उपयोग किया गया है तो हांगकांग-बेलारुस द्वारा भी इसका उपयोग इसी तरह से किया जाता रहा है। दरअसल टेलीग्राम को आजादी की आवाज कहा जाता है। रुस के दो भाईयों पॉवेल ड्यूरोव और निकोलोई ड्यूरोव द्वारा तैयार ओर संचालित इस प्लेटफार्म का दावा है कि वह डाटा शेयर नहीं करता। इस पर प्रसारित संदेशों को कोई तीसरा नहीं देख या पढ़ नहीं सकता। और यही कारण है कि सुरक्षित व गोपनीयता के दावें के चलते इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने वाले ग्रुप इस प्लेटफार्म पर सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सदस्य बनाने, हिंसा फैलाने, पैसा जुटाने, नशीली दवा, हथियार जुटाने, नफरत के संदेश फैलाने आदि आदि असाामाजिक गतिविधियों में प्लेटफार्म का उपयोग किया जाता है। जहां तक टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म की बात है तो केवल 60 कार्मिकों द्वारा संचालित इस प्लेटफार्म पर इस तरह की गतिविधियों की मोनेटरिंग करने, हटाने, कार्रवाई करने की आशा करना बेमानी होगा। ऐसे में एक बार फिर यक्ष प्रश्न यही उभरता है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफार्म आज लोगों की जरुरत बन चुका है तो फिर इन प्लेटफार्मों के संचालकों के लिए एक आदर्श एसओपी जारी करने के साथ ही इन पर असामाजिक, समाज विरोधी, आतंकवादी, भ्रम फैलाने वाली या इसी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता हो गई है। सवाल देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति और सदभावना का है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का समझना होगा। सरकार को भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त प्लेटफार्मों पर रोक या सख्त कार्रवाई करने में किसी तरह की देरी व संकोच नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी मूल भूमिका संवाद, साझा जानकारी, स्वस्थ्य मनोरंजन और एक दूसरे को जोड़ने जैसे मूल्यों को लेकर आगे आना होगा।

अभियान

तपस्वी बालक की सीख और सत्यजीत की लंबी यात्रा

हाईस्कूल का एक सरल, शांत और संवेदनशील बालक अपने विद्यालय के अध्ययन भ्रमण के दौरान पहली बार उस भूमि पर पहुँचा, जहाँ कभी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों ने आख़िरी साँसें ली थीं। हवा में एक अजीब-सी गंभीरता थी, मानो धरती अब भी उन वीरों के कदमों की गूँज सँभाले हुए हो। वह बालक सीढ़ियाँ चढ़कर उस स्मारक के बिल्कुल पास खड़ा हुआ, जहाँ किसी समय में बारूद की गंध, संघर्ष की आवाज़ें और बलिदान की चमक ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। स्मारक की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उसका मन एक पल के लिए ठहर-सा गया। उसके शिक्षक ने शहीदों की कहानियाँ सुनानी शुरू कीं—कैसे किसी ने अपने घर की चौखट छोड़ी, किसी ने अपने पिता के सूखे हाथ चूमकर रणभूमि की ओर कदम बढ़ाए और किसी ने हँसते-हँसते फाँसी के तख़्ते को चूमा। बालक यह सब सुनते हुए भीतर तक पिघल गया। वहाँ लगे पौधों के बारे में भी शिक्षक ने बताया—यह पौधा उन शहीदों की स्मृति में लगाया गया था, यह पौधा उस क्रांतिकारी के नाम पर, जो आख़िरी क्षण में भी अंग्रेज़ों से डटकर लड़ा था। बालक

की आँखें नम थीं, फिर भी उनमें एक अजीब-सी चमक थी—सम्मान, श्रद्धा और भारत माता के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा।

कहानी सुनने के बाद वह धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसने नीचे रखे अपने जूते उठाए, साफ़ किया और पहन लिया। कुछ दूरी पर एक पतली-सी सड़क किनारे बनी सीमेंट की बेंच पर बैठकर वह फिर से प्रतिमा को निहारने लगा। उसे लग रहा था जैसे प्रतिमा उसके दिल में उतर रही हो—एक मौन शिक्षा देती हुई कि श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, आचरण में भी होनी चाहिए। वह ऐसा ही सोच रहा था कि उसकी दृष्टि अचानक कुछ लोगों पर पड़ी। तीन-चार पर्यटक वहाँ आ रहे थे। उनमें से एक ने हैट पहना था, हाथ में कैमरा पकड़ा था, जबकि कुछ लोग सिगार पीते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे।

जूते-चप्पल पहने हुए वे लोग प्रतिमा के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर बालक के मन में एक कसक उठी। उसे लगा कि यह स्थान केवल इतिहास की एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक पवित्र धरोहर है, जहाँ आदर और मर्यादा का पालन होना आवश्यक है। बहुत देर तक वह मौन बैठा रहा, मगर उसकी अंतरात्मा ने उसे विचलित कर दिया। आखिर वह खड़ा हुआ और धीरे-धीरे उन लोगों की ओर बढ़ा। बालक ने उनसे अत्यंत विनम्रता से कहा, "आपको नंगे पैर आना चाहिए था। यह स्थान बहुत पवित्र है। शहीदों की स्मृति को सम्मान देने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम जूते-चप्पल नीचे उतार दें। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की पवित्रता को जाग्रत रखने का तरीका है।"

वह बालक न तो किसी से लड़ने आया था, न किसी को अपमानित करने। उसके शब्दों में एक अद्भुत मासूमियत थी, एक सरल सच्चाई थी। कुछ क्षणों के लिए वे पर्यटक स्तब्ध रह गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा-सा लड़का इतनी कोमलता और दृढ़ता से उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ा देगा। उस क्षण उस परिसर में कोई शोर नहीं था—सिर्फ उस बालक की विनम्र आवाज़ गूँज रही थी, जिसने अपनी शिक्षा, अपने संस्कारों से सीखा हुआ एक गहरा पाठ दुनिया को सुना दिया।

समय बीतता गया। वह बालक बड़ा हुआ। जीवन उसे कोलकाता की गलियों से होते हुए कैमरे की दुनिया में ले गया, जहाँ रोशनी, छाया, भावनाएँ और दृश्य उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने लगे। धीरे-धीरे उसने मानव संवेदनाओं को नए रूप में दिखाने का अपना मार्ग चुना। वही बालक आगे चलकर दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक बना—सत्यजीत रे। और लोग कहते हैं कि जिस दिन उसने शहीद स्थल पर खड़े होकर वह साहसिक, मासूम, किंतु अत्यंत सभ्य सुझाव दिया था—उसी दिन उसके भीतर का कलाकार जाग गया था। क्योंकि कला केवल फ्रेम, रोशनी और कहानी से नहीं बनती—कला की जड़ें उन संस्कारों में होती हैं, जो हमें सही और गलत का बोध कराते हैं, और जो हमें सिखाते हैं कि सम्मान और संवेदना ही मनुष्य को महान बनाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑनलाइन जन शिकायत निवारण के कार्यक्रम 'स्वागत' में उपस्थित रहकर शिकायतों के निवारण का मार्गदर्शन दिया

- मुख्यमंत्री ने किसानों सहित सभी लोगों की समस्याओं का जमीन पर जाकर तथा गहराई से समझकर तत्काल निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए
- मुख्यमंत्री ने तहसील और जिला 'स्वागत' के निर्णयों के स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन और गहन निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश
- राज्य 'स्वागत' में 70 से अधिक नागरिकों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिला 'स्वागत' की 1156 शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही जिला स्तर पर की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में प्रस्तुत शिकायतों और समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गहराई से समझते हुए तथा जमीन पर जाकर उनका शीघ्र निवारण करना आवश्यक है।

बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में शुरू किया गया राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष पहुंचाने के साथ ही समस्या के निवारण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता देकर उनके त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, इसकी मिसाल नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में देखने को मिली।

इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में 70 से अधिक नागरिक अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए आए थे, जिनमें से 4 आवेदकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर सुना। जबकि शेष समस्याओं को मुख्यमंत्री जनसंपर्क इकाई के अधिकारियों ने सुना और कार्रवाई के लिए संबद्ध विभागों तथा जिला स्तर के अधिकारियों को भेजा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित नवंबर महीने के जिला 'स्वागत' के तहत प्राप्त 1156 शिकायतों की निराकरण कार्यवाही जिला स्तर पर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर तहसील और जिला 'स्वागत' की शिकायतों के संबंध में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन और उनकी गहन निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिन तहसीलों और जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या अधिक है, ऐसे जिलों में शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

पोरबंदर जिले के दो गांवों के किसानों ने सुखभादर नदी पर पुल बनाने की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर राज्य 'स्वागत' में मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने उन किसानों के प्रति संवेदना दर्शाते हुए इस पुल को मंजूरी देने के लिए सड़क एवं भवन विभाग के सचिव को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने पोरबंदर के ही एक अन्य अभ्यावेदक को तत्काल उसके भूखंड के निर्धारित क्षेत्रफल के साथ प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने के लिए पोरबंदर कलेक्टर आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद जिला कलेक्टर से कहा कि वे धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के लिए आरक्षित भूमि के चलते धोलेरा तहसील के एक अभ्यावेदक की खेती की जमीन में हुई क्षति-नुकसान के कारण सात-बारह (राजस्व दस्तावेज) में दर्ज नोट को हटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हाल में हुई असाधारण बेमौसम बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए कृषि पैकेज सहायता प्राप्त करने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो।

नवंबर-2025 के इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सर्वश्री धीरज पारेख और राकेश व्यास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।

रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ट्रेन में औचक टिकट जाँच, 161 बिना टिकट यात्रिओं से जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल अपने सम्माननीय यात्रिओं से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील करता है और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न अभियान चलाता है। मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में हाल ही में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी, जिसके अंतर्गत 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19 नवंबर, 2025 को अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रिओं द्वारा अनियमित यानि बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए वडोदरा मंडल के वाणिज्य बिभाग द्वारा रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी। टिकट जाँच दल में वाणिज्य विभाग के मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री पी के झा, श्री रोशन लाल, श्री एम एस चौहान एवं उप मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री तेजकरन एवं मुख्य टिकट कलेक्टर श्री ए के सिंह ने भाग लिया और यात्रिओं द्वारा बिना टिकट यात्रा के मामले पकड़े। इस औचक निरीक्षण में 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

ये उपलब्धियाँ पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में गहन टिकट जाँच अभियानों के माध्यम से बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने और यात्री अनुशासन को बढ़ावा देने के वडोदरा मंडल के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

अजमेर मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के मारवाड़ जं.-आउवा स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज नं. 590 किमी 437/4-5 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग हेतु ब्लॉक लिए जाने के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेन

23 नवंबर 2025 को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

24 नवंबर 2025 को साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

रेगुलेट ट्रेन

22 नवंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14701 श्री गंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस अजमेर-मारवाड़ के बीच 01.00 घंटा देरी से चलेगी।

23 नवंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस पालनपुर-मारवाड़ के बीच 25 मिनट देरी से चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना, मार्ग और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे ने दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान टिकट जांच के क्षेत्र में अपना अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान लगभग 19 लाख बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों का पता लगाते हुए 121.67 करोड़ की राजस्व-राशि अर्जित की गई। इसमे अनबुक्ड लगेज के प्रकरण भी समाविष्ट हैं। यह उपलब्धि गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 80.56 करोड़ की आय की तुलना में 51% की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करती है तथा यह रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 14% अधिक है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर 2025 में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 24 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है, जो इस अवधि का दूसरा सर्वोत्तम मासिक रिकॉर्ड है। पश्चिम रेलवे का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड मई 2022 में स्थापित हुआ था, जब लगभग 26 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद मंडल ने अक्टूबर 2025 में 50 हजार प्रकरणों का संज्ञान लेकर 4 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन दर्ज किया। इसी क्रम में, मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने भी अक्टूबर 2025 में 2.20 करोड़ का उत्कृष्ट राजस्व अर्जित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड स्थापित किया, जो मई 2022 में प्राप्त 2 करोड़ के पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से अधिक है।

अक्टूबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने कई दैनिक राजस्व उपलब्धियों के नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए। पश्चिम रेलवे द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को लगभग 1.40 करोड़ की आय अर्जित की गई। इसी प्रकार 18 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद मंडल ने 38 लाख से अधिक, तथा रतलाम मंडल ने लगभग 16 लाख का राजस्व प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर 2025 को मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने लगभग 16.30 लाख की आय दर्ज की।

ये उपलब्धियां पश्चिम रेलवे द्वारा टिकट रहित एवं अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुशासन को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित व्यापक टिकट जांच अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद एवं वडोदरा क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदों के साथ बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों मंडलों में जारी यात्री सुविधाओं के उन्नयन, चल रही एवं प्रस्तावित परियोजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। बैठक में अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों में प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस दौरान प्रजेंटेशन के माध्यम से अहमदाबाद मंडल पर दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रयासों, मंडल में प्रगति पर विभिन्न रेल परियोजनाओं—जैसे नई रेल लाइनों, नई ट्रेन सेवाओं, मेजर रिडेवलपमेंट स्टेशनों (भुज, अहमदाबाद, साबरमती) तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे अन्य 16 स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी।

साथ ही रेल सुविधाओं, परियोजनाओं, ट्रेनों के नए ठहराव, ट्रेन विस्तार, फेरे बढ़ाने तथा अन्य ढांचागत आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

इस बैठक में माननीय सांसदों में श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा), श्री भरत सिंहजी डाभी (पाटन), श्री मितेशभाई पटेल (आणंद), श्री जशुभाई राठवा (छोटा उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम), श्री नरहरि अमीन (राज्यसभा) तथा श्री मयंकभाई नायक (राज्यसभा) उपस्थित रहेंगे।

रेलवे प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी, RLDA तथा दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह पहल जनप्रतिनिधियों के साथ सहभागिता व सहयोग को बढ़ाकर रेल सुविधाओं के उन्नयन, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी।

कच्छ और सौराष्ट्र के लिए नए निवेश और औद्योगिक अवसरों के द्वार खोलेगा आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

- कच्छ और सौराष्ट्र में तेज़ी से उभरते औद्योगिक एवं निवेश अवसर
- मोरबी, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका और भावनगर पश्चिमी गुजरात के प्रमुख ग्रोथ हब
- द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसः 8–9 जनवरी 2026 को राजकोट में

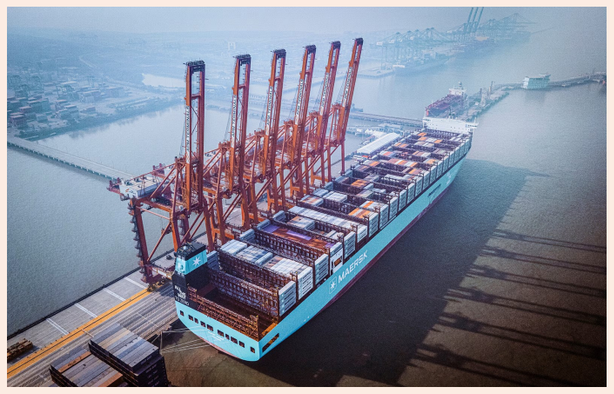

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार कच्छ और सौराष्ट्र के समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन इन दोनों क्षेत्रों में उभर रहे औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। साथ ही, यह पश्चिमी गुजरात में तेजी से बढ़ते निवेश, नए अवसरों और समावेशी विकास की गति को भी रेखांकित करेगा।

क्षेत्रीय विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस

सम्मेलन में सेरामिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, खनिज, ग्रीन एनर्जी, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, पर्यटन और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष चर्चाएं होंगी। रणनीतिक साझेदारियों, नीतिगत प्रोत्साहनों और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से यह आयोजन पश्चिमी पट्टी में सतत् औद्योगिक विस्तार और संतुलित विकास को गति देने का उद्देश्य रखता है।

कच्छ से मोरबी और जामनगर तक: पश्चिमी गुजरात में उभरते नए निवेश केंद्र

कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला, विकसित अवसंरचना, मजबूत बंदरगाह कनेक्टिविटी और विस्तार पाते औद्योगिक गलियारों के कारण आज वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कांडला और मुंद्रा जैसे देश के महत्त्वपूर्ण पोर्ट इसकी आर्थिक क्षमता को और मजबूती देते हैं। पशुपालन, विविध पर्यटन स्थलों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों ने कच्छ को पेट्रोकेमिकल्स, 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए अत्यंत आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है।

मोरबी, जिसे देशभर में सिरेमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यह 900 से अधिक विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से सिरेमिक उद्योग में गुजरात की नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करता है। यह जिला घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में उल्लेखनीय योगदान देता है।

जामनगर, अपनी सशक्त औद्योगिक पहचान के साथ ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ 15,000 से अधिक इकाइयाँ पीतल के महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करती हैं। आम, अमरूद और अनार जैसे उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन ने इसे एग्रो-आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इसकी वैश्विक औद्योगिक क्षमता को और बढ़ाती है।

राजकोट से तटीय जिलों तक: उद्योग, संस्कृति और व्यापार का मजबूत संगम

राजकोट, गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा जिला, देश के मशीन टूल्स और विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी है। MSME विकास, नवीन उद्यमिता और बांधणी-अजरख जैसी पारंपरिक कलाओं ने इसे औद्योगिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाया है।

पोरबंदर, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, मत्स्य उद्योग, मिनरल प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प तथा देश के सबसे बड़े कॉस्टिक सोडा प्लांट के कारण औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र केमिकल्स जैसी संस्थाएँ इस क्षेत्र के औद्योगिक तंत्र को मजबूती देती हैं। देवभूमि द्वारका, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी पावन भूमि होने के साथ-साथ औद्योगिक रूप से भी उल्लेखनीय है। मिथापुर स्थित टाटा केमिकल्स का संयंत्र देश के प्रमुख सोडा ऐश उत्पादकों में शामिल है, जबकि ओखा बंदरगाह मछली उत्पादों, खनिजों और नमक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाता है।

भावनगर, प्याज उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र होने के अलावा अलंग में स्थित विश्व के सबसे बड़े शिप-ब्रेकिंग यार्ड के कारण वैश्विक समुद्री उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोटाद एक उभरता हुआ औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। सुरेंद्रनगर, कपास, सौंफ और नमक उत्पादन में अग्रणी होने के साथ-साथ बंधनी और टांगलिया बुनाई की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है।

जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में कृषि और एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों के साथ-साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिरनार पर्वत जैसी पर्यटन संपदाएँ इन्हें इको-टूरिज़्म और फूड प्रोसेसिंग के नए अवसरों से जोड़ती हैं। अमरेली, जहां देश का पहला निजी क्षेत्र का पिपावाव पोर्ट स्थित है, यह थोक व कंटेनर कार्गो के लिए प्रमुख समुद्री द्वार है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग तथा सीमेंट उद्योग ने अमरेली को सौराष्ट्र की औद्योगिक विविधता में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

8 और 9 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित होगा द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

राजकोट में आयोजित होने वाली आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात सरकार की क्षेत्रीय प्रगति को अगले चरण में ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सतत् औद्योगिक इकोसिस्टम, कौशल विकास और नवाचार पर विशेष फोकस के साथ कच्छ और सौराष्ट्र "विकसित गुजरात-विकसित भारत @2047" की परिकल्पना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

कुर्रम में खून की बारिशः दो मुठभेड़ों में 23 विद्रोही ढेर, पाकिस्तान सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी

(जीएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में एक बार फिर गोलियों की गूँज सुनाई दी। कुर्रम जिले की पहाड़ियों और जंगलों में बुधवार की रात से गुरुवार तक चले सुरक्षा अभियानों ने पूरे इलाके को दहला दिया। पाकिस्तान सेना ने घोषणा की है कि दो अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए, जिनका संबंध कुख्यात संगठन "फितना अल ख्वारिज" से बताया जा रहा है।

घटनाओं की शुरुआत उस समय हुई जब सेना को कुर्रम के एक दुर्गम इलाके में विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में पुख्ता सूचना मिली। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने बताया कि सेना ने तत्काल ऑपरेशन छेड़ा। घेराबंदी के दौरान विद्रोहियों ने तेज़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला। इस भीषण मुठभेड़ में 12 विद्रोही मौके पर ही ढेर हो गए।

लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी इलाके से कुछ ही दूरी पर छिपे विद्रोहियों के दूसरे समूह की जानकारी मिलते ही सेना ने दूसरा अभियान शुरू किया। यह अभियान और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। सुरक्षाबलों ने इस समूह को भी चारों तरफ से घेरकर ज़मीन और पहाड़ी क्षेत्रों में दबाव बढ़ाया। दूसरी मुठभेड़ में 11 और विद्रोही मार गिराए गए।

आईएसपीआर के अनुसार, यह अभियान केवल विद्रोहियों के सफाए भर का प्रयास नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास है जो लंबे समय से क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा था। सेना ने बताया कि इलाके में और भी विद्रोहियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके लिए वृहद तलाशी अभियान लगातार जारी है। पहाड़ियों, जंगलों और आबादी रहित पट्टियों में सुरक्षाबल चप्पा-चप्पा खंगाल रहे हैं। कुर्रम जिला लंबे समय से आतंकी और उग्रवादी गतिविधियों का अड्डा माना जाता रहा है। यहां स्थित भौगोलिक संरचनाएँ—पहाड़ी घाटियाँ, घने जंगल और सीमावर्ती रास्ते—विद्रोहियों को छिपने, regroup करने और हमले की योजना बनाने में सहजता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान सेना इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है।

स्थानीय लोगों के लिए पिछले दो दिनों के हालात भयावह रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट, हेलीकॉप्टरों की उड़ानें और लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों ने वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि सेना का दावा है कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 23 विद्रोही लड़ाकों का मारा जाना सेना की बड़ी सफलता है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। "फितना अल ख्वारिज" जैसे संगठनों की जड़ें गहरी हैं और इनके खिलाफ चल रहा अभियान संभवतः और भी कड़ा होने वाला है।

ट्रंप ने बदली आप्रवासन बहस की दिशा: एच-1बी को अमेरिका की तकनीकी रीढ़ बताया

(जीएनएस)। वाशिंगटन की हवा इन दिनों असामान्य रूप से गर्म है—राजनीतिक और तकनीकी दोनों अर्थों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर अपने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' समर्थकों की उम्मीदों के केंद्र बिंदु रहे हैं, इस बार उसी समर्थन आधार के भीतर एक नई बहस खड़ी कर बैठे हैं। अमेरिकी-सऊदी निवेश मंच में उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम को अमेरिका की तकनीकी जरूरतों का आधार बताया, उससे न केवल उनके आलोचक चौंक गए, बल्कि उनके अपने समर्थक भी असहज दिखाई दिए।

ट्रंप ने मंच से कहा कि अमेरिका की विशाल तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को केवल स्थानीय बेरोजगारों से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एरिज़ोना में प्रस्तावित अरबों डॉलर की चिप फ़ैक्ट्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाएँ केवल उन विशेषज्ञ हाथों से चल सकती हैं, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से अमेरिका तक आते हैं। उन्होंने इसे ही "असली मागा" बताया और कहा कि वैश्विक प्रतिभा को अमेरिका में काम करने देना, देश को मज़बूत करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशी विशेषज्ञ सिर्फ मशीनें नहीं चलाते, वे ज्ञान भी लाते हैं—ऐसा ज्ञान जो आने वाले वर्षों में अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर देश को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रशिक्षण के बाद कई विशेषज्ञ वापस अपने देशों चले जाते हैं, लेकिन उनके छोड़े कौशल और कामकाजी संस्कृति का लाभ वर्षों तक अमेरिका को मिलता रहता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के भीतर तकनीकी प्रतिभा की कमी स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। कई हाई-टेक कंपनियाँ लंबे समय से कहती रही हैं कि खास क्षेत्रों—जैसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरकम्प्यूटिंग, सैटेलाइट टेक—में घरेलू विशेषज्ञों की संख्या जरूरत के मुकाबले बेहद कम है।

ट्रंप ने इस स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को तकनीकी युद्ध में जीतना है, तो उसे वैश्विक विशेषज्ञों की मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए।

लेकिन इस भावनात्मक और व्यावहारिक तर्क के पीछे राजनीतिक झंझावात भी कम नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही लॉरा लूमर और बेनी जॉनसन जैसे नाम एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े आलोचक हैं। उनका आरोप है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों को खतरे में डालता है। वे इसे "अमेरिका फर्स्ट में सेंध" बताते हैं। इन आलोचनाओं को ट्रंप पहले भी खारिज कर चुके हैं और हाल ही में फॉक्स न्यूज़ पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि अमेरिका अभी भी "दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रतिभा संकट" से गुजर रहा है। इस पूरी बहस के बीच एक नई हलचल सितंबर में तब पैदा हुई जब ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा के लिए एक लाख डॉलर तक की फीस का प्रस्ताव रख दिया। इस निर्णय से राजनीतिक माहौल और उद्योग जगत के बीच तनाव और बढ़ गया। जहाँ रिपब्लिकन पार्टी का एक तबका इसे सख़्त आप्रवासन नीति का आवश्यक हिस्सा मानता है, वहीं तकनीकी कंपनियाँ चेतावनी दे रही हैं कि अगर विशेषज्ञों की आवाजाही रोकी गई, तो अमेरिका की तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व पर सीधा असर पड़ेगा। मंच से उतरते समय भी ट्रंप ने वही बात दोहराई—अमेरिका को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने दरवाज़े दुनिया के सामने पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। उनके शब्दों में, "तकनीक की दुनिया सीमाओं से नहीं चलती। अगर अमेरिका अपनी सीमाएँ बहुत कसकर बंद कर लेगा, तो भविष्य किसी और के हाथ चला जाएगा।" अमेरिका की राजनीति में यह बयान आने वाले दिनों में नई बहस को जन्म देगा, लेकिन एक बात अब साफ है—एच-1बी वीज़ा पर लड़ाई केवल आप्रवासन की नहीं, बल्कि अमेरिका के भविष्य की है।

ब्राजील में भारत की गूंज: जलवायु संकट को वैश्विक सुरक्षा खतरा घोषित कर जगाए विश्व नेता

(जीएनएस)। अमेज़न के घने वर्षावनों की नमी से भरी हवा में इन दिनों एक नया तनाव घुला हुआ है—एक ऐसा तनाव, जिसमें पृथ्वी का भविष्य, दुनिया की सुरक्षा और मानव सभ्यता की स्थिरता एक-दूसरे से गुँथी दिखाई देती है। ब्राजील के बेलें शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप-30 में भारत ने जिस स्पष्टता और दृढ़ता से अपना संदेश रखा, उसने दुनिया के नेताओं को नई दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया है। भारत ने साफ कहा कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ वैज्ञानिकों की चिंता या पर्यावरणविदों की चेतावनी नहीं है—यह भविष्य की वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट बन चुका है, जो धीरे-धीरे हर देश की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।

सम्मेलन के दौरान उच्च-स्तरीय बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की आवाज़ जैसे पूरे सभागार में एक चेतावनी की तरह गूंज उठी। उन्होंने याद दिलाया कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम मौसमी घटनाएँ—अनियंत्रित बाढ़ें, लू की मार, अनिश्चित मानसून, सूखी नदियाँ और डूबते तटीय शहर—अब सीमाएँ नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि समुद्र का लगातार बढ़ता स्तर कई छोटे देशों के अस्तित्व को निगलने के कगार पर है, जबकि पानी और खाद्यान्न की कमी दुनिया के बड़े भूभागों को अस्थिर बना रही है। इस अस्थिरता के बीच पलने वाली सामाजिक अशांति और राजनीतिक तनाव भविष्य में किसी भी देश के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकते हैं।

भारत ने इस मंच से पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को यह संकेत दिया कि जलवायु संकट को केवल पर्यावरण के नजरिए से देखना अब पर्याप्त नहीं है। इसे सुरक्षा संकट समझकर ही वैश्विक नीति और रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी। मंत्री ने कहा कि यह समय निष्क्रियता या औपचारिक वक्तव्यों का नहीं, बल्कि एकजुट होकर ठोस कार्रवाई करने का है।

अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों को उनकी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने औद्योगिक क्रांति के बाद सौ-सवा सौ वर्षों तक पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग अपनी प्रगति के लिए किया, उन्हें अब पीछे छूटे देशों को आवश्यक वित्त और तकनीक मुहैया कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत ने फिर दोहराया कि सालाना एक ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त विकसित देशों द्वारा दिया जाना चाहिए—क्योंकि यह उनका वादा है, दया नहीं। भारत के अनुसार बिना वित्त और तकनीक के विकासशील देशों से नेट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद करना अन्यायपूर्ण है।

भारत ने यह भी बताया कि वह स्वयं दुनिया के चुनिंदा बड़े देशों में से है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पहले ही हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली की ओर से यह भरोसा भी जताया गया कि भारत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जलवायु न्याय के सिद्धांतों के बिना कोई भी प्रयास टिकाऊ नहीं हो सकता।

भूपेंद्र यादव ने दुनिया को "लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट"—LIFE—अभियान की ओर आकर्षित किया, जिसे भारत एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहता है। उनका संदेश स्पष्ट था कि जब तक जीवनशैली पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगी, तब तक तकनीक और वित्त भी अधूरी कोशिश साबित होंगे।

सम्मेलन स्थल पर मौजूद ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन को एक उभरती सुरक्षा चुनौती के रूप में स्वीकार करने पर सहमति जताई। यह सहमति इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में जलवायु परिवर्तन को महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है।

अमेज़न के दिल में बसे बेलें शहर में 10 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन अब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारत के संदेश ने साफ कर दिया है कि असली चर्चा अब सिर्फ तापमान कम करने की नहीं, बल्कि दुनिया को अस्थिरता के भंवर से बचाने की है। और इस बार, यह चेतावनी उस देश से आई है जिसने हमेशा जलवायु न्याय को मानवता का प्रश्न माना है।

लाल किला धमाका: चार आरोपी 10 दिन की एनआईए रिमांड पर, आतंकी साज़िश की परतें खुलने लगीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को गिरफ्तार किए गए चार और आरोपितों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में पेश किए गए इन आरोपितों में पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ. आदिल अहमद रतहर, लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद और शोपियां के मुफ़्ती इरफ़ान वागे शामिल हैं। अदालत ने एनआईए द्वारा मांगी गई रिमांड को स्वीकार करते हुए एजेंसी को सभी से गहन पूछताछ की अनुमति दे दी है। इस केस में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी आरोपी एनआईए की हिरासत में हैं, जिससे पूरे मॉड्यूल के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के उजागर होने की संभावना बढ़ गई है।

इस मामले में इससे पहले श्रीनगर से पकड़ा गया जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश भी 10 दिनों की रिमांड पर है। दानिश को मॉड्यूल का एक अहम तकनीकी कड़ी माना जा रहा है, जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नबी की तैयारियों में सहायता की थी। एनआईए की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दानिश ड्रोन को मॉडिफाई करने, रॉकेट जैसे उपकरण बनाने और कार बम मॉड्यूल को तकनीकी सहयोग देने में शामिल था। एजेंसी का दावा है कि उमर नबी ने कई महीनों तक उसे आत्मघाती हमला करने के लिए ब्रेनवॉश किया, लेकिन आर्थिक और धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए उसने अंततः आत्मघाती हमलावर बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में ठहराया गया था, जहां मॉड्यूल के सदस्य उसे जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास जिस आई-10 कार में विस्फोट हुआ, वह आरोपित आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत थी। माना जा रहा है कि कार को ट्रेनिंग, परीक्षण और विस्फोट की अंतिम तैयारी के लिए मॉड्यूल द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह घटना राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और इसी कारण केंद्र सरकार ने एनआईए को केस की जांच सौंपते हुए इसे 'हाई प्रायरिटी टेरर केस' घोषित किया था।

एनआईए का कहना है कि गिरफ्तार आरोपितों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण और विदेशी संचार के कुछ संकेत मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच जारी है। एजेंसी को शक है कि यह मॉड्यूल बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो सीमा पार से संचालित आतंकी संगठनों के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच अधिकारी बताते हैं कि अब तक की पूछताछ में कई परतें खुली हैं, लेकिन अभी भी इस मॉड्यूल की फंडिंग, कम्युनिकेशन चैनल और मास्टरमाइंड की भूमिका पर और जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिमांड के दौरान ऐसे तथ्य सामने आएंगे, जो इस आतंकी साज़िश को पूरी तरह समझने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस भयावह बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 13 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और 32 लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी से जूझ रहे हैं।

बचपन का सबसे काला वर्ष: 2024 में युद्धों ने 12,000 मासूमों की जान ली

(जीएनएस)। लंदन से आई एक ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। सेव द चिल्ड्रन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि बीता वर्ष 2024 बच्चों के लिए इतिहास का सबसे घातक साल साबित हुआ। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में करीब 12,000 बच्चे युद्धों, बम धमाकों और हिंसक संघर्षों में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उतने ही टूटे हुए परिवारों, उजड़े सपनों और असहाय बचपन की चीखों की गवाही है। 2006 के बाद से रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी, पर इतने भयावह आंकड़े इससे पहले कभी सामने नहीं आए। 2020 की तुलना में यह संख्या 42 प्रतिशत अधिक है, जो बताती है कि दुनिया का हिंसा-मानचित्र बच्चों के लिए लगातार और घातक होता जा रहा है।

पिछले कुछ दशकों तक युद्धों का खतरा बच्चों पर मुख्यतः भूख, कुपोषण, महामारी और टूटे-बिखरे स्वास्थ्य ढाँचों के रूप में मंडराता था, लेकिन आज के युद्धों की प्रकृति बदल चुकी है। लड़ाई अब सीमाओं से उठकर सीधे शहरों की गलियों में उतर आई है। गाजा की तंग आबादी वाली बस्तियों में, सूडान के संघर्षग्रस्त इलाकों में, यूक्रेन के स्कूलों, अपार्टमेंट ब्लॉक और अस्पतालों में होने वाली गोलीबारी और बमबारी से बच्चे प्रत्यक्ष रूप से निशाना बन रहे हैं। जहाँ कभी खेलते हुए बच्चों की हँसी गूँजती थी, आज वहाँ ड्रोन की गूँज, मिसाइलों की तेज़ गर्जना और ग्रेनेड के धमाकों का धुआँ फैला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में बच्चों के हताहत होने के 70 प्रतिशत मामले विशेष रूप से विस्फोटक हथियारों—मिसाइलों, ग्रेनेड, बम—के कारण हुए। पिछले वर्षों का औसत 59 प्रतिशत था, जो इस बढ़ते खतरे की भयावह दिशा की ओर इशारा करता है।

सेव द चिल्ड्रन यूके की वरिष्ठ सलाहकार नरमीना स्ट्रिशेनेट्स ने दुनिया की इस स्थिति को "बचपन के सुनियोजित विनाश" की तरह बताया। उन्होंने कहा कि मिसाइलें उन जगहों को भी नहीं छोड़ रहीं, जिन्हें कभी सुरक्षित आश्रय माना जाता था—बच्चों के सोने के कमरे, उनके खेलने की जगहें, उनके स्कूल, यहाँ तक कि अस्पताल भी। घर, जो सुरक्षा और अपनापन का प्रतीक होते थे, अब राख और मलबे में बदल रहे हैं। स्कूल, जहाँ कल के नागरिक तैयार होते थे, अब जमीन पर टूटे टुकड़ों की तरह बिखरे पड़े हैं। बच्चों की शारीरिक बनावट भी उन्हें अधिक जोखिम में डाल देती है। छोटे शरीर, विकासशील अंग और नाजुक हड्डियाँ किसी भी विस्फोट की ताकत को झेल नहीं पातीं। एक ही धमाका कई बच्चों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है—कुछ मौत के आगोश में चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं, वे गहरे घाव, शारीरिक विकृति और मानसिक आघात के साथ जीवनभर संघर्ष करते रहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक युद्ध सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, वह बचपन, भरोसा और भविष्य भी तोड़ देता है।

इन सबके बीच गाजा की स्थिति सबसे अधिक दिल दहलाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष में दुनिया में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक संघर्ष गाजा पट्टी में हुआ। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इज़रायल द्वारा किए गए सैन्य अभियान में अब तक करीब 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। यह संख्या सिर्फ आँकड़ा नहीं, बल्कि हर दिन ढहते घरों, मलबे में दबी छोटी हथेलियों और हर पल गूँजती असहाय चीखों का प्रतिनिधित्व है। गाजा का नक्शा अब सिर्फ भूगोल नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बाल-त्रासदी क्षेत्र में बदल गया है।

दिल्ली विस्फोट केस में बड़ी कार्रवाई: श्रीनगर से चार और गिरफ्तार, साजिश की परतें खुलने लगीं

(जीएनएस)। दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट ने जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया था, उसी गंभीरता के साथ जांच की रफ्तार अब और तेज होती दिख रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को श्रीनगर में एक सुनियोजित कार्रवाई के दौरान चार महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दबोच लिया, जिन पर इस हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। इन नई गिरफ्तारियों के साथ मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या छह तक पहुंच चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि विस्फोट के पीछे फैला नेटवर्क पहले अनुमान से कहीं बड़ा और जटिल हो सकता है।

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जारी पेशी वारंट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एनआईए ने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुलवामा के डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ स्थित डॉ. शाहीन सईद और शोपियां निवासी

मुफ़्ती इरफ़ान अहमद वागे शामिल हैं। इन सभी पर शुरुआती जांच के दौरान यह संकेत मिले हैं कि वे न केवल साजिश से जुड़ी चर्चाओं में शामिल थे, बल्कि हमले से संबंधित विभिन्न चरणों की योजना और क्रियान्वयन में भी संदेह के दायरे में आते हैं।

इससे पहले एनआईए ने दो और आरोपितों—आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी—को हिरासत में लिया था। आमिर पर वह कार अपने नाम पर दर्ज करवाने का आरोप है, जिसका उपयोग कथित रूप से हमले में किया गया। वहीं जसीर वानी उर्फ दानिश पर हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता देने का गंभीर संदेह है। दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है और एजेंसी का मानना है कि इनसे प्राप्त जानकारी पूरे नेटवर्क की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

एनआईए के अनुसार, इस हमले से जुड़े हर व्यक्ति और हर कड़ी तक पहुंचना फिलहाल एजेंसी की प्राथमिकता है। शुरुआती तथ्य बताते हैं कि मामला केवल कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे संगठित और प्रशिक्षित नेटवर्क काम कर रहा था। यही कारण है कि एजेंसी ने जांच की गति बढ़ा दी है और तकनीकी तथा फॉरेंसिक दोनों मोर्चों पर तेजी से काम हो रहा है।

इसी बीच जम्मू में एक अलग लेकिन संबंधित हलचल तब दिखाई दी जब जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार को प्रसिद्ध दैनिक 'कश्मीर टाइम्स' के कार्यालय पर छापा मारा। अखबार पर आरोप है कि उसने देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रकाशित की और कुछ रिपोर्टों में ऐसे तत्वों का महिमामंडन किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल माने जा सकते हैं। एसआईए ने दफ्तर में मौजूद कंप्यूटरों, दस्तावेज़ों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की और संबंधित सामग्री को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए सील कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, चूंकि मामला संस्थान और इसके प्रमोटरों दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है, इसलिए आगे चलकर उनसे पूछताछ की संभावना भी बनी हुई है।

दोनों घटनाओं ने मिलकर कश्मीर से दिल्ली तक फैले सुरक्षा तंत्र में हलचल का माहौल पैदा कर दिया है। जहां एनआईए दिल्ली विस्फोट की तह तक पहुंचने में जुटी है, वहीं एसआईए की कार्रवाई यह संकेत देती है कि सुरक्षा एजेंसियाँ अब न केवल आतंकवाद से जुड़े प्रत्यक्ष नेटवर्क बल्कि परोक्ष समर्थन और वैचारिक प्रोत्साहन देने वाले हर तत्व पर भी पैनी निगाह रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है, और जैसे-जैसे साजिश की परतें खुलेंगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने नए सवाल और नई चुनौतियाँ भी खड़ी होती जाएँगी।

सोशल मीडिया को कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी: अश्विनी वैष्णव का वैश्विक मंच से स्पष्ट संदेश

(जीएनएस)। सिंगापुर के ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक डिजिटल जगत को एक कड़े और निर्णायक संदेश के साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ संवाद के मंच नहीं रह गए, बल्कि समाज की सोच, मत और व्यवहार को प्रभावित करने वाला बड़ा सामर्थ्य बन चुके हैं। ऐसे में उन पर प्रकाशित हर सामग्री—चाहे वह वीडियो हो, तस्वीर, डीपफेक, अपुष्ट दावा या भ्रामक पोस्ट—की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म्स को खुद लेनी होगी। मंत्री के अनुसार, डिजिटल माध्यम पर फैली गलत जानकारी समाज में अविश्वास, तनाव और अस्थिरता पैदा कर रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि टेक कंपनियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो।

कार्यक्रम के दौरान बातचीत में मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की डिजिटल और आर्थिक नीतियाँ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत हैं कि तेज़ी से बढ़ता, स्थिर, विश्वसनीय और कानून-सम्मत नियामक ढांचा कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित मुद्रास्फीति और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता ने देश को निवेशकों के लिए अभूतपूर्व अवसरों वाली भूमि बना दिया है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाले न्यू इकोनॉमी फोरम में आमंत्रित करते

हुए कहा कि भारत न सिर्फ अवसरों से भरा है, बल्कि एक सुरक्षित और स्पष्ट नियामक दृष्टि भी प्रदान करता है।

डिजिटल शासन पर बोलते हुए वैष्णव ने भारत के अभिनव "टेक्नो-लीगल मॉडल" का विशेष उल्लेख किया, जिसे आधुनिक तकनीक और मजबूत कानूनी ढाँचे के संतुलन के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून सिद्धांत-आधारित है, इसलिए यह तेजी से बदलती तकनीकों के अनुकूल आसानी से ढल सकता है और नवाचार को भी बाधित नहीं करता। उनके अनुसार, भविष्य उन्हीं देशों का है जो नियमों और नवाचार—दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, न कि किसी एक को दूसरे पर थोपकर।

मंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि भारत में काम कर रही किसी भी विदेशी या घरेलू टेक कंपनी को भारतीय संविधान, कानूनों, सामाजिक विविधताओं और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना होगा। यह सिर्फ कानूनी अपेक्षा नहीं है, बल्कि देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की मूल शर्त है। उन्होंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म को यह समझना होगा कि भारत जैसा विशाल और विविधता से भरा देश डिजिटल कंटेंट को लेकर अतिरिक्त संवेदनशीलता रखता है, और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण निर्माण में उनकी भूमिका अनिवार्य है।

फोरम के इस सत्र ने वैश्विक डिजिटल आर्थिक विमर्श में भारत की मुखर और स्पष्ट भूमिका को और मजबूत किया। वैष्णव का संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया के लिए चेतावनी और सुझाव दोनों है, जो डिजिटल माध्यम के विस्तार के साथ नई चुनौतियों और नई संभावनाओं में कदम रख रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी ही व्यवस्था को ठुकराया-राज्यपालों को समय बाँधना असंवैधानिक, राष्ट्रपति के सवालों पर ऐतिहासिक राय

(जीएनएस)। दिल्ली की ठंडी सुबह में जब सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ अपने फैसले पर पहुँची, तो देश की संवैधानिक बहसों में एक नया मोड़ दर्ज हो गया। अदालत ने अपने ही दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए उस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय देने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई थी। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका की अपनी सीमाओं को रेखांकित करता है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे, कार्यपालिका की स्वायत्तता और संविधान के मूल सिद्धांत—checks and balances—को भी दुबारा स्पष्ट करता है।

कहानी की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने से हुई। यह एक दुर्लभ संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अदालत की सलाह मांगते हैं। यहाँ सवाल यह था कि जब संविधान ने राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं तय की, तो क्या अदालत अपने आदेशों से ऐसी टाइमलाइन बनाकर उन्हें मानने के लिए बाध्य कर सकती है? तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने 10 विधेयकों को 'डीम्ड असेंट' यानी मंजूर मान लिया था, क्योंकि गवर्नर ने लंबे समय तक उन पर निर्णय नहीं दिया था। इसने पूरे देश में राज्यपालों की भूमिका और अदालत की सीमाओं पर भारी बहस छेड़ दी थी।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने 10 दिनों तक चलने वाली दलीलों को सुनने के बाद साफ कर दिया कि अदालतें न तो राज्यपाल के विवेक का समय निर्धारित कर सकती हैं और न ही राष्ट्रपति की। पीठ ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक को सदन में वापस भेजे, उस पर अपनी राय दे या उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाए। लेकिन अदालत इस विवेकाधिकार को आकर सीमित नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार यह निर्णय कार्यपालिका का है और इस पर कोई जज समय-सीमा थोप दे, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ठेस पहुँचाता है।

जजों ने यह भी कहा कि अदालत का

'डीम्ड असेंट' वाला दृष्टिकोण पूरी तरह गलत था। किसी बिल को 'स्वतः स्वीकृत' मान लेना ऐसा है जैसे अदालत राज्यपाल की भूमिका खुद निभाने लगे। यह न केवल संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, बल्कि उस मूल अवधारणा के भी खिलाफ है जिसमें हर संवैधानिक पद की अपनी स्वतंत्र जिम्मेदारी तय है। अदालत ने कहा कि इससे न्यायपालिका का दायरा अनुचित रूप से बढ़ जाता है और कार्यपालिका की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, जो संविधान के आत्मा के अनुकूल नहीं है। हालाँकि अदालत ने एक संतुलित रास्ता भी दिखाया। उसने कहा कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बिलों को रोककर नहीं रख सकते। लोकतंत्र अवरोध पर नहीं, संवाद पर चलता है—अदालत का यही संदेश था। अगर कोई राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाने में अत्यधिक देरी करता है और कोई कारण भी नहीं बताता, तो अदालत सीमित न्यायिक समीक्षा के तहत यह निर्देश दे सकती है कि वह एक निश्चित अवधि में निर्णय ले। लेकिन वह निर्णय क्या होना चाहिए—बिल को मंजूरी मिले या नहीं—इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील हिस्सा यह था कि अदालत को अपनी ही डबल बेंच के फैसले की समीक्षा करनी पड़ी। उस फैसले ने एक तरह से गवर्नर की भूमिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप कर दिया था—कुछ ऐसा जो देश के संवैधानिक ढांचे में असहजता पैदा कर रहा था। इसी फैसले ने राष्ट्रपति को मजबूर किया कि वे अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च अदालत से मार्गदर्शन मांगें। और आज, अदालत ने न केवल अपने पुराने फैसले को असंवैधानिक घोषित किया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि संविधान की भाषा और मंशा किसी न्यायिक कल्पना से बड़ी है। दिल्ली की अदालत में दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय आगे आने वाले वर्षों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों की दिशा तय करेगा। यह संदेश स्पष्ट है—न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, निर्माता नहीं। और राज्यपाल, जो अक्सर राजनीतिक विवादों में फंस जाते हैं, उन्हें भी यह याद रखना चाहिए कि संघवाद में संवाद ही समाधान है, देरी और अवरोध नहीं।

कलोल स्टेशन का तेज़ी से हो रहा है पुनर्विकास

शहर के दोनों छोर और सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाला 40 फीट चौड़े फूट ओवर ब्रिज के निर्माण से यात्रियों की आवाजाही होगी और अधिक सुगम

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के कलोल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तेज़ी से किया जा रहा है। लगभग 44.22 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। पुनर्विकास के अंतर्गत स्टेशन भवन का उन्नयन, नया एंट्री गेट एवं पोर्च, भव्य फ़साड, विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया तथा पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में सौंदर्यीकरण हेतु आकर्षक भित्तिचित्र (Murals) भी लगाए जा रहे हैं।

स्टेशन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 70 और 80 वर्ग फीट चौड़े दो नए एंट्री गेट तथा समान आकार के दो निकास द्वार विकसित किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की आवाजाही और अधिक सुविधाजनक होगी। इसके साथ ही लगभग 14,000 वर्ग फीट का विस्तृत स्टेशन भवन क्षेत्र आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20,000 वर्ग फीट का कवर शेड तैयार किया जा रहा है, जबकि 2,370 वर्ग फीट का विशाल वेटिंग हॉल यात्रियों को आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा।

स्टेशन परिसर में वाहनों की पार्किंग क्षमता बढ़ाते हुए 18,750 वर्ग फीट में 55 चार पहिया एवं 110 दोपहिया वाहनों के लिए सुसंगठित पार्किंग विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षित और सहज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगभग 7,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का 40 फीट चौड़ा और 173 लंबा फूट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो शहर के दोनों छोर और सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ते हुए सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म विस्तार, कवर शेड और दूसरे प्रवेश द्वार के विकास का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत कई प्रमुख कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पुराने स्टेशन भवन को हटाने के बाद बुकिंग ऑफिस, वेटिंग हॉल एवं पैनल रूम को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। नए मुख्य भवन की नींव, प्रथम एवं द्वितीय मंज़िल का RCC कार्य पूरा हो चुका है। प्लास्टर, टाइल्स एवं फ़साड क्लैडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अन्य फिनिशिंग कार्य जारी हैं। स्काईवॉक एवं लिफ्ट निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2,000 यात्री कलोल स्टेशन का उपयोग करते हैं और 24 ट्रेनें यहां नियमित रूप से रुकती हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में चार प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को भी स्वीकृति प्रदान की **गई है, जिनमें शामिल हैं:**

- गाड़ी संख्या 20959/60 वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस
- गाड़ी संख्या 16507/08 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस
- गाड़ी संख्या 15269/70 मुजफ्फरपुर–साबरमती एक्सप्रेस
- गाड़ी संख्या 12215/16 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

इन चार ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे आवागमन और भी सुगम एवं सुविधाजनक होगा। इससे व्यापार, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

भविष्य की आवश्यकताओं और क्षेत्र की लगातार बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कलोल स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 40,000 यात्रियों की आवाजाही को संभालने की क्षमता के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों से न सिर्फ यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा बल्कि स्थानीय समुदाय को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ भी प्राप्त होगा। कलोल स्टेशन का यह पुनर्विकास न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि आधुनिक रेल अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। पुनर्विकसित कलोल स्टेशन आने वाले समय में कलोल एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए स्मार्ट, सुगम और आधुनिक रेल परिवहन का प्रमुख केंद्र बनेगा।